

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता – बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस

आर्म्स अपील संख्या 08/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोंडेन्टस
सुभान खान पुत्र भाई खान, जाति मुसलमान निवासी बडी ढाणी बाप, तहसील बाप जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर।

आर्म्स अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरुद्ध
आदेश दिनांक 13.7.2011 द्वारा पारित जिला कलेक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट, सिरौही

उपस्थिति:-




1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह राठौड
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक:- 20.5.2019

प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट द्वारा एक आवेदन पत्र 12 बोर गन के शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के समक्ष पेश किया। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जिसमें शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंसा नहीं की गयी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का आवेदन पत्र दाखिल दफ्तर कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गयी है।


डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

आर्म्स अपील संख्या 08/2018 सुभान खा बनाम राजस्थान सरकार

हमने उपस्थित अपीलान्त के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्त के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्त ने अपनी कृषि एवं पशुधन की सुरक्षा के लिये 12 बोर गन के लिए आवेदन किया था। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने अपनी टिप्पणी में उल्लेखित किया है कि अपीलान्त का चरित्र अच्छा है, अपीलान्त के विरुद्ध को आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, अपीलान्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की किन्हीं धाराओं के अन्तर्गत पाबन्ध नहीं किया गया है। अन्त में बिना कारण दिये हथियार दिये जाने की अनुशंसा नहीं की गयी।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट, के आधार अपीलान्त का शस्त्र अनुज्ञापत्र संबंधी आवेदन बिना ठोस कारण दर्शाये खारीज कर दिया। जो कि विधि अनुसार उचित नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर, जोधपुर को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अपीलान्त द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त ने 12 बोर गन के लिए आवेदन किया था। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी को हथियार दिये जाने की अनुशंसा नहीं की गयी। अपीलान्त ने अपनी कृषि एवं पशुधन की सुरक्षा के लिये 12 बोर गन के लिए आवेदन किया था। जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण ने अपनी टिप्पणी में उल्लेखित किया है कि अपीलान्त का चरित्र अच्छा है, अपीलान्त के विरुद्ध को आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, अपीलान्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की किन्हीं धाराओं के अन्तर्गत पाबन्ध नहीं किया गया है। अन्त में बिना कारण दिये हथियार दिये जाने की अनुशंसा नहीं की गयी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ने पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण से



Handwritten signature
दिविजयल कविशर्मा
जोधपुर

आर्म्स अपील संख्या 08/2018 सुभान खा बनाम राजस्थान सरकार

प्राप्त रिपोर्ट, के आधार एवं प्रार्थी के आवेदन पत्र में जान माल की सुरक्षा के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे की ग्यात हो की अपीलान्ट को का किस प्रकार का खतरा (Threat perception) है। इसी दृष्टिकोण को एवं आर्म्स अधिनियम में दिये गये प्रावधानों, शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने संबंधी राज्य/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को मध्यनजर रखते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह उचित है। मैं अपीलाधीन आदेश से सहमत हूँ, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांत खारीज की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.2011 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बाबूलाल कोठरी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर